परिशिष्ट–"अ"[22/9/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 50

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा–3 के प्रावधान के अंतर्गत जांच आयोग का गठन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2003 से 2018 तक घटित विभिन्न गंभीर घटनाओं, हादसों, तनाव अथवा जन असंतोष की जांच हेतु गठित जांच आयोगों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना कमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त एवं अप्राप्त	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर की मृत्यु–घटना का जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–10/2004/1–10 दिनांक 06/08/2004	मान. श्री गुलाब सिंह सोलंकी, जिलाएवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर।	दिनांक 30.04.09 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर दिनांक 25.11.2017 को रखा गया।
2.	दतिया जिले की सिंध नदी घटना जांच आयोग 2006	अधिसूचना कमांक–एफ–24–6/2006/1–10 दिनांक 13/10/2006	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पाण्डेय।	दिनांक 21.03.2007 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर दिनांक 22.07.2014 को रखा गया।
3.	जिला रीवा के जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री के परिसर में गोली चालन जांच आयोग	अधिसूचना कमांक–एफ–24–7/2007/1–10 दिनांक–31/10/2007	माननीय सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह।	दिनांक 18.08.2011 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर दिनांक 12.12.2014 को रखा गया।
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–22–15/2005/1–10 दिनांक 08/02/2008	माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन।	दिनांक 15.09.2012 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।
5.	सरदार सरोवर परियोजना, के फर्जी रजिस्ट्री जांच आयोग	अधिसूचना कमांक–एफ–24–20/2008/1–10 दिनांक 08/10/2008	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. झा।	दिनांक 29.07.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखा गया।
6.	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग भोपाल	अधिसूचना कमांक–एफ–24–9/2010/1–10 दिनांक 25/08/2010	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एल. कोचर।	दिनांक 24.02.2015 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
7.	जिला भिण्ड गोली चालन	अधिसूचना कमांक–एफ–24	माननीय श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ,	दिनांक 31/12/2017	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-1

	घटना न्यायिक जांच आयोग।	–1/2012/1–10 दिनांक दिनांक 12/07/2012	सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	हेतु गृह विभाग को दिनांक 17/1/2018 को भेजा गया है।
8.	रतनगढ़ जिला दतिया दुर्घटना जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–14/2013/1–10 दिनांक 15/10/2013	माननीय श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश।	दिनांक 22.03. 2014 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर दिनांक 12.12. 2014 को रखा गया।
9.	जिला सिंगरौली थाना बैढन में हुई गोली चालन घटना की न्यायिक जांच।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–25/2013/1–10 दिनांक 16/12/2013	माननीय श्री आर.एस. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	दिनांक 30.09. 14 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखा गया।
10.	गोसपुरा नं. 02 मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–3/2015/1–10 दिनांक 17/08/2015	श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	दिनांक 09.01. 2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
11.	पेटलावद जिला झाबुआ में हुये विस्फोट घटना जांच आयोग।	अधिसूचना क0–एफ–24–5–2015–1–10 दिनांक 15.09. 2015	श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायलय।	दिनांक 11/12/2015 को जांच प्रतिवेदन मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त।	दिनांक 06/04/2016 प्रकरण मूलतः गृह विभाग भेजा गया। कार्यवाही प्रचलित।
12.	भोपाल केन्द्रीय जेल से 8 बंदियो के भागने की घटना जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–7/2016/1–10 दिनांक 07/11/2016	श्री एस.के. पाण्डे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय।	दिनांक 24.08. 2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	दिनांक 20.06. 2018 से जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखा गया है।
13.	पेटलावद में मोहर्रम जुलूस को रोके जाने की घटना जांच आयोग।	अधिसूचना कमांक–एफ–24–9/2016/1–10 दिनांक 20/11/2016	श्री राजकुमार पाण्डे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	दिनांक 20.11. 2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	दिनांक 11 जुलाई 2019 को जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखा गया है।
14.	मंदसौर में घटित घटना जांच आयोग।	अधिसूचना क0–एफ–24–6/2017/1–10 दिनांक 12.06. 17	श्री जे.के. जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय।	जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.06. 2018 को प्राप्त।	दिनांक 14.06. 2018 को गृह विभाग जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग. कक्ष-१०